दैनिक जागरण

आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखता है

फिर वही जुमलेबाजी

यह समझ आता है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से विपक्षी दलों को कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला रास नहीं आया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे इस फैसले की आड़ लेकर सरकार को गरीब विरोधी ठहराने की कोशिश करें। हैरानी यह है कि वे यही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस फैसले को प्रधानमंत्री की ह्यूस्टन में होने वाली रैली से तो जोड़ा ही, यह भी रेखांकित किया कि यह सब शेयर बाजार को गिरने से बचाने के लिए किया गया। उनके मंतव्य को और स्पष्ट किया कपिल सिब्बल ने, जिन्होंने यह टिप्पणी की कि इस फैसले से केवल अमीरों को फायदा होगा। उनकी मानें तो सरकार ने गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेसी नेताओं की ये टिप्पणियां यही बताती हैं कि वे एक बार फिर सूट-बूट की सरकार सरीखे किसी जुमले की तलाश में हैं। उन्हें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि जिस समय वे सरकार को अमीर हितैषी और गरीब विरोधी साबित करने में लगे हुए थे, लगभग उसी समय मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला कर रही थी। बेहतर हो कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस यह समझे कि अर्थव्यवस्था नारेबाजी की राजनीति से नहीं चलती और जहां तक गरीबी की बात है तो वह तभी दूर हो सकती है जब उद्योग-धंधों का तेजी से विकास हो। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला लेकर सरकार ने यही करने का प्रयास किया है। अगर विपक्ष को यह कदम ठीक नहीं लगा तो फिर उचित यह होता कि वह जुमलेबाजी करने के बजाय अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने वाले उपाय सुझाता।

निःसंदेह गरीबों की चिंता की ही जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें निर्धनता की खाई से उबारे बगैर देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन कम से कम अब तो इस नतीजे पर पहुंच ही जाना चाहिए कि कारोबार जगत को गरीब विरोधी करार देकर गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। इस बात को जिस दल को सबसे बेहतर तरीके से समझना चाहिए वह कांग्रेस ही हो सकती है, क्योंकि आर्थिक सुधारों का श्रीगणेश उसी ने किया था। विडंबना यह है कि वह जानबूझकर हकीकत से अनजान बने रहना चाहती है। इससे भी खराब बात यह है कि वह आर्थिक मामलों में उस वामपंथी सोच से ग्रस्त होती जा रही है जो दुनिया भर में नाकाम साबित हो चुकी है। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के फैसले के बहाने मोदी सरकार को गरीब विरोधी ठहराने की कोशिश इसलिए हास्यास्पद है, क्योंकि उसने अपने पहले कार्यकाल में गरीबों को राहत देने के लिए जितने कदम उठाए उतने शायद ही किसी सरकार ने उठाए हों।

नहीं लिया सबक

उत्तराखंड में एक बार फिर यह साबित हो गया कि अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। सरकार की नाक के नीचे अंतरिम राजधानी देहरादून में शहर के बीचोंबीच जहरीली शराब के सेवन से हुई आधा दर्जन मौतों ने सरकारी तंत्र की कलई खोल कर रख दी। सात महीने पहले बीते फरवरी माह में रुड़की के उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे दस गांवों में जहरीली शराब पीने से 47 मौत हुई थी, लेकिन दिल दहलाने वाली उक्त घटना से सबक नहीं लिया गया। उस समय भी विभिन्न स्तरों पर जांच की गई थी। तब जांच के बाद व्यवस्था को सुधारने और जहरीली शराब के प्रचलन पर रोक लगाने की दिशा में तत्परता दिखाई गई थी। नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा। शराब के अवैध कारोबार, खासतौर पर जहरीली शराब के धंधे की तह तक सरकार पहुंच नहीं पाई या जानने के बावजूद आंख मूंदने की प्रवृत्ति बदस्तूर जारी है। पहले माना जा रहा था कि कच्ची और जहरीली शराब की चपेट में दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों के गांव ही हैं, लेकिन देहरादून की घटना इस मायने में ज्यादा चौंकाने वाली है कि शासन के आला अफसरों और पुलिस मुख्यालय को भी महज एक किमी की दूरी पर फूल-फल रहे अवैध धंधे की भनक तक नहीं थी। यह कानून व्यवस्था के साथ ही खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। एक ओर सरकार सुशासन, कानून व्यवस्था चाक-चौबंद और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है, दूसरी ओर इस घटना ने इन दावों को ही जमीन दिखा दी। कच्ची शराब की तस्करी भ्रष्टाचार की तस्दीक कर रही है। पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका तो और संदेहास्पद है। पुलिस शुरुआती दौर में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर लीपापोती में लिप्त रही। ये जानकारी सामने आना आश्चर्यजनक है कि पहले हुई मौतों को डेंगू से होने वाली मौत करार देने की कोशिश भी की गई। इस घटना के बाद सरकार ने संबंधित क्षेत्र के पुलिस और आबकारी महकमे के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। कई मंचों पर यह बात कही जा चुकी है कि देहरादून में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। इस पर सख्ती से रोक लगाने को कदम उठे होते तो जहरीली कच्ची शराब की बिक्री पर भी संभवतः काफी पहले ही अंकुश लग जाता। इस मामले में जिला प्रशासन के साथ ही सरकार की भी किरकिरी होने से बच जाती। इस मामले में लीपापोती के बजाय उचित पड़ताल कर गुनाहगारों पर सख्ती की जाए ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

उद्योग जगत भी अपनी जिम्मेदारी निभाए

संजय गुप्त

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के फैसले के बाद उद्योग जगत को चाहिए कि वह एकजुट होकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय हो

देश में मंदी की आहट के बीच जब उद्योगपतियों में निराशा का भाव घर कर रहा था तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा करके न केवल उद्योग जगत को हर्षोल्लास से भर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह वह कदम है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच वर्ष में पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर सकती है और साथ ही भारत तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बना रह सकता है। भारत में विदेशी निवेश की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कॉरपोरेट टैक्स की ऊंची दर थी। जो निवेश चीन या अन्य पूर्वी एशियाई देशों में होता था वह अब नई दरों के कारण भारत की ओर आकर्षित होगा। इस फैसले ने मोदी शासन के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप को भी बल प्रदान किया है, क्योंकि एक अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित होने वाली मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों पर सेस और सरचार्ज मिलाकर अब 17.01 फीसद कॉरपोरेट टैक्स ही लगेगा। यह अभी तक 29.12 प्रतिशत था। 2014 के आम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था के लिए जो रोडमैप दिया था उसमें टैक्स दरें कम कर उन्हें दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने की बात की गई थी। बावजूद इसके किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो घोषणा बजट में नहीं की गई वह चालू वित्त वर्ष के बीच में ही कर दी जाएगी।

मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत मिल रहे थे। पहले फिसलता हुआ ऑटोमोबाइल उद्योग और फिर जीडीपी के गिरते हुए आंकड़े आर्थिक सुस्ती को ही बयान कर रहे थे। हालांकि पिछले तीन सप्ताह से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गईं, लेकिन माहौल नहीं बदल रहा था। अब इस तगड़ी खुराक से स्थिति पूरी तरह परिवर्तित हो गई है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के निवेशकों ने इसका स्वागत किया है। इसे बीते 20 वर्षों का सबसे बड़ा फैसला करार दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को ऐतिहासिक कदम करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार भारत को व्यापार के लिए बेहतर स्थान वाला देश बनाने और समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों को बेहतर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चूंकि यह फैसला रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने वाला है इसलिए उसने सबकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ध्यान रहे कि जब रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो मांग को भी बल मिलता है। यह फैसला इसका परिचायक है कि प्रधानमंत्री देश की आर्थिक उन्नति को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अपनी इसी प्रतिबद्धता के तहत वह हरसंभव उपाय कर रहे हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि सरकार के जिस कदम का उद्योग जगत के साथ आर्थिक मामलों के लगभग सभी विशेषज्ञ स्वागत कर रहे हैं उस

अवधेश राजपूत

पर राहुल गांधी तंज कसना जरूरी समझ रहे हैं। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को प्रधानमंत्री के ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम से जोड़ते हुए कहा कि कोई भी इवेंट उस आर्थिक संकट को छिपा नहीं सकता, जिसमें हाउडी मोदी ने भारत को डाल दिया है। राहुल गांधी के इसी तंज को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के एक अन्य नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने अमीरों को फायदा पहुंचाया और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया। साफ है कि वह गरीबों के बहाने वामपंथी दलों वाली राजनीति कर रहे हैं। उन्हें यह याद होना चाहिए कि आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में यही कहा था कि देश में अब दो ही जातियां रह गई हैं-एक गरीब और दूसरे, गरीबी दूर करने वाले। क्या कांग्रेस यह नहीं जानती कि उद्योग-धंधों के विकास से ही गरीबी दूर करने का काम सही तरह से हो सकता है?

इस पर हैरत नहीं कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा होते ही शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आई। इस दौरान ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी खासी तेजी आई और रुपया भी मजबूत हुआ। हालांकि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले इस फैसले से सरकारी खजाने पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा, लेकिन इससे राजकोषीय घाटा मामूली रूप से ही बढ़ने का अंदेशा है। हाल में रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। यह राशि नई घोषणाओं की मद में बढ़ रहे खर्च में समायोजित होगी। जब यह तय माना जा रहा है कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती से मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्र में तेजी आएगी तब सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल करना होगा। अभी देश के जीडीपी में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का योगदान 15-17 प्रतिशत है, जबकि 65-70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में केवल सब्सिडी और डीबीटी ही पर्याप्त नहीं इसलिए कृषि क्षेत्र में भारी निवेश के साथ अन्य आवश्यक कदम भी उठाने होंगे। इसलिए और भी, क्योंकि मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया हुआ है।

कॉरपोरेट टैक्स कटौती का फैसला करके सरकार ने उद्योगपतियों का मनोबल तो बढ़ाया ही है, आयकर के ई-असेसमेंट की योजना शुरू करने की घोषणा कर कारोबारियों के सिर पर लटकती टैक्स टेररिज्म की तलवार को भी हटाया है। इसके तहत अब किसी को भी आयकर अधिकारी के सामने व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होना पड़ेगा। अब यह आवश्यक है कि उद्योग जगत अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अपने उत्पादों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सक्रिय हो। अभी भारतीय उत्पाद कई मायनों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में कमजोर साबित होते हैं। इसी कारण चीनी उत्पाद भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं। चूंकि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला अप्रैल से प्रभावी होगा इसलिए घरेलू कंपनियों को बहुत लाभ होने जा रहा है। उन्हें इस पैसे का इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट पर करना चाहिए ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। अगर हमारी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में खरा उतरना है तो उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करनी ही होगी।

इसी तरह अब जब सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर किए जाने वाले खर्च का दायरा बढ़ा दिया है तो फिर अनुसंधान को भी गति मिलनी चाहिए। ध्यान रहे कि अनुसंधान किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि की नींव बनते हैं। मोदी सरकार कॉरपोरेट जगत को रियायतें देने के साथ ही कारोबारी माहौल को और सुगम बनाने के लिए सक्रिय है। ऐसे में उद्योग जगत को एकजुट होकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगे आना होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अतीत में यह देखने में आया है कि उद्योगपति अपनी हर समस्या के लिए सरकार को कोसने लगते हैं। उद्योग क्षेत्र को इस मनःस्थिति से उबरना होगा और नई सोच के साथ देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में जुटना होगा।

response@jagran.com

दुनिया का ध्यान खींचने वाली दोस्ती

तरुण विजय

भारत-अमेरिका के बीच अभूतपूर्व मित्रता का ह्यूस्टन अध्याय सामरिक महत्व से भी कहीं बढ़कर है

देश के साथ दुनिया का ध्यान खींचने वाली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ह्यूस्टन सभा के अवसर पर हम भारतीयों को 126 साल पहले स्वामी विवेकानंद के उस संबोधन का स्मरण भी करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका...। इसके बाद सभा भवन कई मिनटों तक तालियों से गूंजता रहा था और भारत के प्रति दुनिया की दृष्टि बदल गई थी। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे और उन्होंने वहां दिए गए अपने संबोधन के माध्यम से विश्व में भारत के धर्म और अध्यात्म का जो डंका बजाया उसकी अनुगूंज अभी तक सुनाई देती है। माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की ह्यूस्टन सभा भी दुनिया को भारत की ओर न केवल आकर्षित करने वाली, बल्कि उनके नजरिये को भी बदलने वाली साबित होगी। नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में हिंदुस्तान की शक्ति और सामर्थ्य के साथ देश के सवा अरब लोगों के नए सपनों और नए भारत की गूंज से विश्व को अचंभित कर सकते हैं।

भारत-अमेरिका दोस्ती का ह्यूस्टन अध्याय उस समय रचा जा रहा है जब कुछ ही दिन बाद भारत में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री रूस में थे और उसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। चीनी राष्ट्रपति की प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले भारत और अमेरिका के मध्य अभूतपूर्व मित्रता का यह अध्याय सामरिक महत्व से भी बढ़कर है। चीन ने हाल में कश्मीर मसले पर पाक ही साथ दिया। ऐसे में जब चीन सामरिक चुनौती के रूप में सामने हो तो ह्यूस्टन सभा का महत्व और बढ़ जाता है। मोदी की ह्यूस्टन सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप की सहभागिता न तो अचानक है और न ही केवल औपचारिकतावश। इसके बहुत गहरे कूटनीतिक और सामरिक अर्थ हैं। ट्रंप को भी ह्यूस्टन सभा में शामिल लाभ होने का लाभ होगा ही। अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप भारतीय समुदाय के समर्थन का भरपूर उपयोग करना चाहेंगे। भारत-अमेरिका की प्रगाढ़ता को प्रकट करने वाले इस आयोजन की महत्ता इससे भी समझी जा सकती है कि इसका प्रसारण हिंदी, अंग्रेजी के साथ स्पेनिश भाषा में भी किया जाएगा। वास्तव में ह्यूस्टन में वह होने जा रहा है जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। यह विराट और विश्वव्यापी प्रसिद्धि वाला अभूतपूर्व कार्यक्रम उस समय हो रहा है जब भारत ने मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को नया रूप दिया है जिस पर पाक केवल खिसियानी बिल्ली की तरह होकर रह गया है।

ट्रंप और मोदी की जोड़ी जब ह्यूस्टन में 50 हजार से ज्यादा भारतीयों के सामने और विश्व में करोड़ों दर्शकों द्वारा देखे जाते हुए दोस्ती की अभिव्यक्ति करेगी तो इसका असर क्या होगा, यह सोच कर दुश्मन परेशान और मित्र बाग-बाग होंगे। पूरी दुनिया में इस सभा का बहुत गहरा असर होने वाला है। पाकिस्तान पहले से ज्यादा मुस्लिम देशों और साथ ही पश्चिमी देशों के मध्य अलग-थलग हो जाएगा। उसे इसका अहसास जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा कि आखिर वह केवल चीन के भरोसे कब तक चलेगा? दुनिया उस पर भरोसा नहीं कर रही है। इसी कारण उसे हर वैश्विक मंच पर मात खानी पड़ रही है। इस आयोजन की एक बड़ी बात यह होगी कि विश्वव्यापी भारतीय समाज का सम्मान और अभिमान ही नहीं, उसका मनोबल भी असीम आकाश तक पहुंचेगा। हर भारतीय चाहे वह अमेरिका में हो या अफ्रीकी अथवा अरब देशों में अथवा यूरोप में, ह्यूस्टन की सभा से प्रभावित और रोमांचित होगा। संयुक्त राष्ट्र के हाल के आंकड़े के अनुसार दुनिया के विभिन्न देशों में डेढ़ करोड़ से अधिक भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से भारतीय सबसे आगे हैं। ह्यूस्टन की सभा उनके लिए एक विशेष अवसर होगी। यह सभा दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों की पहचान को बल तो देगी ही, उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। विदेश स्थित भारतीयों का कद अपने-अपने देश में बढ़ने का सीधा असर उनकी अपनी आर्थिक स्थिति में नए अवसरों की उपस्थिति के रूप में हो सकता है।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | अमेरिका में एशियाई देशों के कितने प्रवासी

(संख्या लाख में-आंकड़े 2017 तक)

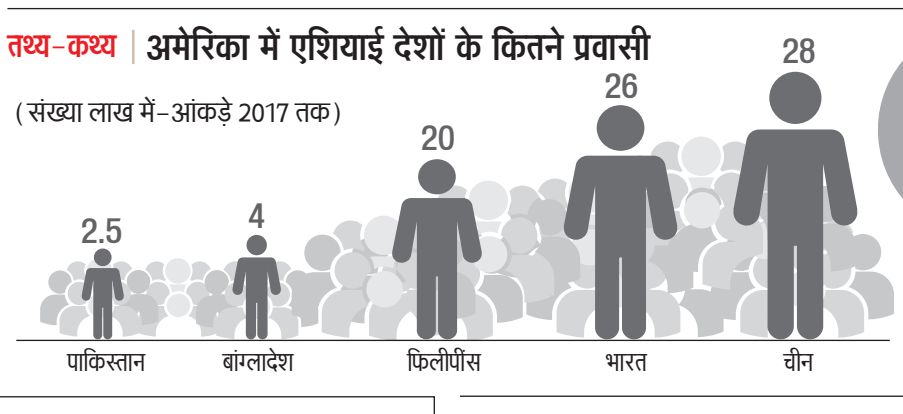

ऊर्जा

सेवा का प्रकाश

हम अपनी महत्वाकांक्षाओं से इतने बंध गए कि इस स्वार्थ में हमारी संवेदना भी खो गई हैं। आज स्वयं को सुरक्षित रखने के सिवाय किसी का कोई चरित्र नहीं है। ऐसी स्थिति में सेवा और सहयोग के आयाम कैसे विकसित हों? इसलिए जरूरी है दिशा बदलने की। परार्थ और परमार्थ चेतना जगाने की। दोनों हाथ एक साथ उठेंगे तो एकता, संगठन, सहयोग, समन्वय और सौहार्द की स्वीकृति होगी। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो क्रांतिकारी का कारवां बनेगा। यही शक्ति है समाज में व्याप्त असंतुलन एवं अभाव को समाप्त करने की। सेवाजनित लाभ कभी कहीं नहीं जाता। एक कहावत है-'करें सेवा मिलें मेवा।' समाज में उजालों की जरूरत आज ज्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि वास्तविक उजाला जीवन को खूबसूरती प्रदान करता है। वस्तुओं को आकार देता है, शिल्प देता है, रौनक एवं रंगत प्रदान करता है। उजाला इंसान के भीतर ज्ञान का संचार करता है और अंधकार को खत्म कर जीवन को सही मार्ग दिखाता है। नकारात्मक दृष्टिकोण दूर कर सकारात्मक दृष्टि और सोच प्रदान करता है।

खुली आंखों से सही-सही देख न पाएं तो समझना चाहिए कि यह अंधेरा बाहर नहीं, हमारे भीतर ही कहीं घुसपैठ किए बैठा है जबकि जीवन में उजालों की कमी नहीं हैं। महावीर का त्याग, राम का राजवैभव छोड़ वनवासी बनना और गांधी का अहिंसक जीवन-ये उजालों के प्रतीक हैं जो भटकाव से बचाते रहे हैं। आचार्यश्री महाप्रज्ञ ने कहा है प्राचीनकाल में स्वार्थ कम तथा स्नेह व सौहार्द ज्यादा था। आज उसमें कमी आई है। इसका एक कारण है धन के प्रति आकर्षण और नकारात्मक चिंतन। जहां सकारात्मक चिंतन का विकास होता है वहां संबंधों में सौहार्द बढ़ता है। इसके लिए जरूरी है व्यक्ति अपने भीतर झांके। अंतर्दृष्टि को जागृत कर नया प्रकाश प्राप्त करें।' सेवा की विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ जुड़कर उसी नए प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, वह ईश्वरत्व का बीज है, स्वयं से स्वयं के साक्षात्कार का मार्ग है।

ललित गर्ग

बाढ़-रोधी फसलों की तलाश

मुकुल व्यास

यह उन इलाकों के लिए अच्छी खबर है जहां वर्षा की अवधि और तीव्रता में वृद्धि से फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है

बाढ़ में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। प्रमुख फसलों में सिर्फ धान की ही फसल बाढ़ को झेल पाती है, लेकिन एक नए शोध से यह स्थिति बदल सकती है। यह दुनिया के उन इलाकों के लिए एक अच्छी खबर है जहां वर्षा की अवधि और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। इस शोध में यह जानने की कोशिश की गई कि जलमग्न होने के बाद धान की तुलना में दूसरी फसलों की क्या स्थिति होती है। धान की फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली जंगली प्रजातियों से तैयार की गई थी, जहां उसने जलमग्न खेतों के अनुसार खुद को ढाल लिया था। इस अनुकूलन के लिए जिम्मेदार जीन दूसरे पौधों में भी मौजूद होते हैं, लेकिन इन जीनों ने जड़ों के जलमग्न होने की स्थिति में सक्रिय होने के लिए खुद को विकसित नहीं किया है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में आनुवंशिकी की प्रोफेसर और इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका जूलिया बेली-सेरेस का कहना है कि हम धान के पौधों के बारे में अर्जित जानकारी का लाभ उठा कर दूसरे पौधों में भी जीनों को सक्रिय करना चाहते हैं, ताकि ये पौधे जलमग्न स्थिति को झेलने में समर्थ हो सकें। उन कोशिकाओं की जांच की गई जो जड़ों के छोर में वास करती हैं। बाढ़ में सबसे पहली प्रतिक्रिया जड़ों की तरफ से होती है। जड़ों के छोर और टहनी ऐसे अंग हैं जहां पौधे में विकसित होने की सामर्थ्य होती है। इन हिस्सों में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पौधे को बाढ़ की स्थिति को झेलने में मदद कर सकती हैं।

गहन जांच करते हुए शोधकर्ताओं ने जड़ों के छोर की कोशिकाओं के जीनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसका मकसद यह पता लगाने का था कि पानी से ढके होने तथा ऑक्सीजन से वंचित होने पर क्या ये जीन सक्रिय होते हैं और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं। एक प्रमुख शोधकर्ता मॉरिसियो रेनोसो का कहना है, 'हमने यह जानने की कोशिश की, कि अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए डीएनए कोशिका को क्या निर्देश देता है। एक अन्य शोधकर्ता ने तो यहां तक कहा कि यह पहला अवसर है जब बाढ़ के खिलाफ पौधे की प्रतिक्रिया को बारीकी से समझा गया है। बाढ़ अनुकूलन में शामिल जीनों को 'सबमर्जेंस अप-रेगुलेटेड फैमिलीज' कहा जाता है।

इन शोधकर्ताओं ने चावल के जीन-समूहों का विश्लेषण किया और जलमग्न स्थिति में जीनों के व्यवहार पर प्रयोग किए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के शोधकर्ताओं ने यही प्रयोग टमाटर की प्रजातियों के साथ किए। जलमग्नता के प्रयोगों में टमाटर की सभी प्रजातियों में एसयूआरएफ जीन सक्रिय जरूर हुए, लेकिन उनकी आनुवंशिक प्रतिक्रिया चावल की भांति कारगर नहीं थी। रेगिस्तानी जमीन में उगने वाले जंगली टमाटर जलमग्नता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक सूखे की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थितियों का सामना कर सकने वाली फसलों पर अलग से अध्ययन हो रहा है। सूखे की तुलना में पौधों की बाढ़ प्रतिक्रिया पर बहुत कम अध्ययन हुआ है। अतः यह शोध ज्यादा अहमियत रखता है।

(लेखक विज्ञान मामलों के जानकार हैं)

सियासत और आस्था

सत्ता और सियासत के रंग भी बड़े दिलचस्प होते हैं। खासकर राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। यह कहावत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर काफी हद तक फिट बैठती है। दीदी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप सूबे में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच संग्राम का एक बड़ा मुद्दा रहा है। मगर सियासत में दिखाई देने वाली इस तस्वीर से इतर निजी तौर पर ममता बनर्जी की धार्मिक आस्था काफी गहरी है। लंबे अर्से बाद इस हफ्ते दिल्ली आईं दीदी ने पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में इसकी झलक भी दिखाई। दरअसल सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मेल-मुलाकातों में हुई अनौपचारिक चर्चाओं का दीदी ने बिल्कुल खुलासा नहीं किया। अपने अगले दौरे में बेबाक चर्चा का वादा किया तो किसी ने पूछा क्या दुर्गापूजा बाद वह आएंगी? इस पर छूटते ही दीदी ने कहा कि दुर्गापूजा ही नहीं 'छठपूजा' तक वह सूबे से बाहर नहीं जाएंगी। फिर दीदी ने बताया कि अभी से नहीं बीते कई वर्षों से वह छठपूजा में शामिल होती आई हैं और आस्था के इस पर्व पर व्रतियों के बीच जाती हैं। इसीलिए अगली बार दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम तो छठपूजा के बाद ही बनेगा।

फैसलों की सही टाइमिंग

सरकार के पिछले कुछ फैसलों की टाइमिंग की सटीकता

राजरंग

इस कदर है कि इंडस्ट्री पूरी तरह खुद को गदगद महसूस कर रही है। अर्थव्यवस्था की सुस्त होती रफ्तार को देखते हुए सभी आर्थिक मंत्रालय तमाम संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस बार नौकरशाही से लेकर राजनीतिक नेतृत्व की यही कोशिश है कि जिस मुद्दे पर फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसका एलान तुरंत कर दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को इंडस्ट्री प्रमुखों के साथ हुई बैठक में भी यही हुआ। दिन भर चली बैठक में कंपनियों ने कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की मांग रखी और रात होते-होते वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी। सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह के मुताबिक ऐसा करने का असर सकारात्मक होता है। इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि जिन फैसलों को लेने में कोई मतभेद नहीं हैं, उनकी घोषणा में कोई देरी करना ठीक नहीं है।

अंगड़ी की अड़चन

एक तेजतर्रार अफसर किसी भी मंत्री की छवि बना सकता है। यही सोचकर रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी ने दानिक्स के एक युवा अफसर को अपना ओएसडी बनाया था। कुछ ही दिनों में इस अफसर ने रेल भवन में ऐसा दबदबा दिखाया कि न केवल अंगड़ी की अहमियत बढ़ गई, बल्कि मीडिया में अंगड़ी की कवरेज बढ़ने लगी। इससे रेलवे के कुछ अफसर परेशान हो गए। उन्होंने बिना देरी किए आनन-फानन इस अफसर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। नतीजतन, दो महीने की अल्प अवधि में ही अफसर की रुखसती के आदेश जारी हो गए। अब रेल राज्यमंत्री के दफ्तर की हनक भी खत्म हो गई है। वरना अंगड़ी का कोई न कोई बयान आता रहता था और उत्तर भारत का मीडिया उसे जोरशोर से कवर करता था, परंतु अब अंगड़ी अपने गृह राज्य कर्नाटक तक सिमट कर रह गए हैं।

चिराग तले अंधेरा

पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रियता का परचम लहरा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भूलने वाले झारखंड के एक कैबिनेट मंत्री का वीडियो भाजपा मुख्यालय के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामचंद्र चंद्रवंशी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं और 17 सितंबर को मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। भाजपा पदाधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आम जनता मोदी-मोदी के नारे लगा रही है तो अपनी ही पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री का नाम कैसे भूल सकता है, लेकिन वीडियो को कोई कैसे झुठला सकता है। वीडियो में रामचंद्र चंद्रवंशी 69वें जन्मदिन की बधाई से शुरुआत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोलने के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी नाम याद नहीं आता है। गजब की बात यह है कि मंत्री महोदय प्रधानमंत्री का नाम भूलने के लिए खुद को नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराने लगते हैं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।